गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 330
दि. 03.04.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

गुजरात में AAP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, अरविंद केजरीवाल ने CM भूपेंद्र पटेल को लिखा पत्र

गुजरात की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही गिरफ्तारियों को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है और आरोप लगाया है कि पंचायत और नगर पालिका चुनावों से पहले सुनियोजित तरीके से उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

केजरीवाल ने अपने पत्र में दावा किया कि पिछले तीन महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के 160 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आने वाले समय में 10 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है। उनके मुताबिक, यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही है, ताकि चुनावों से पहले पार्टी की सक्रियता को खत्म किया जा सके।

उन्होंने लिखा कि पिछले 30 वर्षों से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन अब जनता भ्रष्टाचार, अत्याचार और कथित दमनकारी नीतियों से परेशान हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी खुद को एक ईमानदार, निडर और देशभक्त पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, जो भाजपा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। यही कारण है कि राज्य में पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, और इसी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

केजरीवाल ने हाल की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गिरफ्तारियों का एक खास पैटर्न सामने आ रहा है। उनके अनुसार, कई मामलों में पहले झगड़े की स्थिति पैदा की जाती है, फिर पुलिस बिना निष्पक्ष जांच के सीधे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज देती है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस पहले से ही तैयार रहती है और किसी के फोन का इंतजार करती है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है।

उन्होंने खंभालिया की घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि 31 मार्च 2026 को दीपक सिंह पर कथित रूप से हमला किया गया, लेकिन जब वह शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो उल्टा उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह पोरबंदर में 30-31 मार्च की रात पवन और जगदीश के साथ कथित तौर पर स्कूटी सवार ने विवाद किया, जिसके बाद पुलिस ने बिना विस्तृत जांच के दोनों पर धारा 307 (हत्या के प्रयास) लगा दी और उन्हें जेल भेज दिया।

जामनगर की एक अन्य घटना में नवीन काकरान, मुन्ना कुमार, आलोक सिंह, पुनीतराज और प्रियव्रत के साथ भी ऐसा ही हुआ। आरोप है कि एक मामूली टक्कर के बाद हुए विवाद में पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर ही गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने कहा कि इन घटनाओं में एक समानता दिखाई देती है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है।

अपने पत्र में केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर ये स्कूटर सवार कौन हैं, जो हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकरा जाते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है जैसे किसी योजना के तहत इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस पहले से ही एकतरफा कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों में हमलावरों को छोड़ दिया जाता है, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है।

उन्होंने गुजरात पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिना उचित जांच के इस प्रकार की कार्रवाई न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उनके कई कार्यकर्ताओं पर झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज किए गए हैं, ताकि उन्हें लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर रखा जा सके।

इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की मांग की है, ताकि वे सीधे इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें और राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस मामले को गंभीरता से लेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह विवाद और गहरा सकता है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ वर्षों में राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में यह मुद्दा चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है।

केजरीवाल ने अपने बयान के अंत में कहा कि गुजरात की जनता सब कुछ देख रही है और वह किसी भी प्रकार की तानाशाही या दबाव के आगे झुकेगी नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा—क्या पूरी 6 करोड़ की आबादी को जेल भेजा जा सकता है? उनका कहना है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और सही समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी।

इस बीच, भाजपा या राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे ने गुजरात की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है।

मालदा में चुनावी अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कानून-व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव से जुड़े सात अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की चुनावी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में Supreme Court of India की कड़ी टिप्पणी ने स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि अधिकारियों को करीब नौ घंटे तक बंधक बनाए रखा गया, उन्हें खाना-पानी तक नहीं दिया गया और यह सब एक सुनियोजित तरीके से किया गया प्रतीत होता है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की घटनाओं का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना और न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना हो सकता है।

इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में Surya Kant, Joymalya Bagchi और Vipul M Pancholi शामिल रहे। पीठ ने राज्य प्रशासन की भूमिका पर भी सख्त नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी घटना यह दर्शाती है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर पड़ रही है। अदालत ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और अन्य संबंधित अधिकारियों से उनकी कथित निष्क्रियता पर जवाब मांगा है, जिससे साफ है कि कोर्ट इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।

घटना की जड़ में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर फैला असंतोष बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सात चुनाव पर्यवेक्षक मालदा के एक बीडीओ कार्यालय में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। इनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने कार्यालय को घेर लिया। देखते ही देखते स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अधिकारियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और उन्हें घंटों तक वहीं रोके रखा गया।

यह विरोध केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अगले दिन भी इसका असर दिखाई दिया। गुरुवार को नारायणपुर स्थित बीएसएफ कैंप के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे-12 को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध जताया गया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा, लेकिन हालात देर तक नियंत्रण में नहीं आ सके।

इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें निष्पक्षता और सुरक्षा सर्वोपरि होती है। ऐसे में यदि चुनाव से जुड़े अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो यह व्यवस्था पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं दर्शातीं, बल्कि यह सामाजिक असंतोष और राजनीतिक तनाव का भी संकेत हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने जैसी समस्याएं यदि समय रहते हल नहीं की जातीं, तो वे बड़े स्तर पर विरोध और अस्थिरता का कारण बन सकती हैं।

अब इस पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं—एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार और प्रशासन पर स्थिति को संभालने का दबाव। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि जांच और कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मौतें: आंकड़ों ने खोली कड़वी सच्चाई, खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा संकट

नई दिल्ली। विदेशों में बेहतर रोज़गार और आर्थिक स्थिरता की तलाश में हर साल लाखों भारतीय अपने घर-परिवार से दूर जाते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए सरकारी आंकड़ों ने इस उम्मीद भरे सफर के एक बेहद चिंताजनक और दर्दनाक पहलू को उजागर कर दिया है। Ministry of External Affairs द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 37,740 से अधिक भारतीय श्रमिकों की विदेशों में मौत हो चुकी है। इसका अर्थ यह है कि औसतन हर दिन 20 से अधिक भारतीय श्रमिक विदेशी धरती पर अपनी जान गंवा रहे हैं।

यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की त्रासदी का प्रतीक है, जिनके अपने बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। 29 जनवरी को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री Kirti Vardhan Singh ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इन मौतों के कारणों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर इन मौतों के पीछे क्या वास्तविक कारण हैं—कार्यस्थल की खराब स्थितियां, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, मानसिक दबाव या फिर अन्य कोई कारण।

साल-दर-साल आंकड़ों पर नजर डालें तो समस्या की गंभीरता और स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2021 में 8,234 भारतीय श्रमिकों की मौत दर्ज की गई, जो सबसे अधिक है। इसके बाद 2022 में यह संख्या घटकर 6,614 हुई, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 2023 में 7,291, 2024 में 7,747 और 2025 में 7,854 मौतों के साथ यह आंकड़ा फिर लगातार बढ़ता गया। यह ट्रेंड साफ संकेत देता है कि स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है और जोखिम लगातार बना हुआ है।

इन मौतों का सबसे बड़ा केंद्र खाड़ी देश बने हुए हैं, जहां भारतीय श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या काम करती है। आंकड़ों के मुताबिक, कुल मौतों में से 86 प्रतिशत से अधिक मामले खाड़ी देशों से जुड़े हैं। United Arab Emirates में सबसे अधिक 12,380 मौतें दर्ज की गईं, जो अकेले ही एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके बाद Saudi Arabia में 11,757 मौतें हुईं। इसके अलावा Kuwait (3,890), Oman (2,821), Qatar (1,760) और Malaysia (1,915) में भी बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों की जान गई।

यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि खाड़ी देश भारतीय श्रमिकों के लिए सबसे बड़े रोजगार केंद्र माने जाते हैं। निर्माण, तेल-गैस, घरेलू कार्य और अन्य श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लाखों भारतीय काम करते हैं। लेकिन कई बार उन्हें कठिन कार्य परिस्थितियों, अत्यधिक गर्मी, लंबे कार्य घंटों और सीमित श्रमिक अधिकारों का सामना करना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

मौतों के साथ-साथ शोषण और दुर्व्यवहार की बढ़ती शिकायतें भी एक बड़ा संकेत हैं कि समस्या केवल स्वास्थ्य या दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकारों का पहलू भी जुड़ा हुआ है। 2021 से 2025 के बीच भारतीय दूतावासों और मिशनों को कुल 80,985 शिकायतें प्राप्त हुईं, जो कार्यस्थल पर शोषण, वेतन न मिलना, पासपोर्ट जब्त करना, अमानवीय व्यवहार और अन्य समस्याओं से संबंधित थीं। इन शिकायतों में भी United Arab Emirates शीर्ष पर रहा, जहां से 16,965 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके बाद कुवैत, ओमान और सऊदी अरब का स्थान रहा। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों जैसे मलेशिया और मालदीव से भी बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आई हैं।

यह पूरा परिदृश्य एक गहरे सामाजिक और नीतिगत मुद्दे की ओर इशारा करता है। एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए केवल आंकड़े पेश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें विदेशी नियोक्ताओं के साथ सख्त श्रम समझौते, श्रमिकों के लिए बेहतर बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं, आपातकालीन सहायता प्रणाली और दूतावासों की सक्रिय भूमिका शामिल होनी चाहिए। साथ ही, विदेश जाने से पहले श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण और जागरूकता देना भी बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने अधिकारों और संभावित जोखिमों के बारे में पहले से जानकारी रख सकें। अंततः, यह मुद्दा केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि मानव जीवन और गरिमा का है।

असम चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव, राहुल गांधी ने जारी किया 11 संकल्पों वाला घोषणापत्र

असम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक माहौल तेज़ होता जा रहा है, और इसी बीच Rahul Gandhi ने गुरुवार को बोकाजान में एक बड़ी चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया। इस अवसर पर उनके साथ Gaurav Gogoi समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यह घोषणापत्र कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें राज्य के विकास, पहचान और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख मुद्दों को केंद्र में रखा गया है।

घोषणापत्र में कुल 11 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिनमें शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना, राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का विकास, औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना, ग्रामीण और शहरी विकास को संतुलित करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और "सुरक्षित असम" का निर्माण जैसे संकल्प शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह दस्तावेज केवल वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि असम के भविष्य की एक विस्तृत रूपरेखा है।

इससे पहले कांग्रेस ने 29 मार्च को पार्टी अध्यक्ष Mallikarjun Kharge के दौरे के दौरान 'पांच गारंटी' भी जारी की थीं, जिन्हें अब इस विस्तृत घोषणापत्र के साथ जोड़कर जनता के सामने रखा गया है। पार्टी का दावा है कि ये गारंटी और संकल्प मिलकर राज्य के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे।

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना तय है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और घोषणापत्रों के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।

रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने असम की विविधता को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि असम एक "फूलों का गुलदस्ता" है, जहां अलग-अलग धर्म, जाति और विचारधारा के लोग मिलकर रहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि देश की असली ताकत जनता के हाथ में हो और हर वर्ग को शासन में बराबर भागीदारी मिले।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण का है, जहां फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाएं। इसी संदर्भ में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 244(ए) का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रावधान असम की जनता को अधिक अधिकार और स्वायत्तता देने के लिए लाया गया था, जिससे राज्य को न तो केवल गुवाहाटी से और न ही दिल्ली से नियंत्रित किया जाए, बल्कि स्थानीय लोगों को निर्णय लेने की शक्ति मिले।

अपने भाषण में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा की सोच असम को केंद्र से नियंत्रित करने की है, जबकि कांग्रेस स्थानीय सशक्तिकरण में विश्वास करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यही दोनों पार्टियों के बीच मूलभूत वैचारिक अंतर है।

रैली के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी तीखे राजनीतिक बयान दिए, जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi और अन्य वैश्विक नेताओं का उल्लेख किया। हालांकि, इस तरह के बयान चुनावी माहौल को और अधिक गरमाने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती हैं।

कुल मिलाकर, कांग्रेस का यह घोषणापत्र असम चुनाव में पार्टी की दिशा और दृष्टि को स्पष्ट करता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इन वादों और दावों को किस रूप में स्वीकार करते हैं और आगामी चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं।

संपादकीय

जिंदगी निगलती भीड़

पिछले दिनों वाराणसी में मोबाइल चोरी के संदेह में एक किशोर की पीट-पीट कर हत्या करने की हृदयविदारक घटना सामने आई। घटना कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही, साथ ही भीड़ की बर्बरता की कहानी भी कहती है। क्या एक बच्चे की जिंदगी मोबाइल से सस्ती है? सवाल समाज की बढ़ती आक्रामकता पर भी है। एक ओर हम समाज में कानून का शासन चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कानून हाथ में लेकर किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। निस्संदेह, यदि किसी व्यक्ति की अपराध में शामिल होने की आशंका भी है तो उसे पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अराजक तरीके से मार-पीटकर किसी की हत्या कर देने का अधिकार भीड़ को कैसे मिल सकता है? सवाल ऐसी घटनाओं पर शेष समाज की उदासीनता का भी है। जब उस किशोर को पीटा जा रहा था तो आसपास से गुजरने वाले लोग क्यों उसे बचाने नहीं आए? हाल के दिनों में महज शक के आधार पर लोगों को मौत के घाट उतारने व घायल करने की घटनाएं आम हो गई हैं। यह हमारे समाज के लिये भी चिंता का विषय है क्योंकि निहित स्वार्थी तत्व अकसर निर्दोष लोगों को जाति व संप्रदाय के नाम पर अपने बहुलता वाले इलाके में शिकार बना लेते हैं। प्रश्न यह भी है कि इस तरह की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकारों की तरफ से जमीनी स्तर पर कारगर कदम उठाने की पहल क्यों नहीं होती? जाहिर बात है कि व्यक्ति विशेष को शक के आधार पर निशाना बनाने वाले लोगों में कानून का डर न के बराबर ही होता है। साथ ही आसपास के लोगों का महज तमाशबीन बना रहना भी भीड़ के अराजक व्यवहार को बढ़ावा देता है। वाराणसी की घटना में जिस तरह किशोर को घर से बुलाकर सड़क पर पीटा गया और लोग खामोश रहे, परेशान करने वाला घटनाक्रम ही है। निश्चित रूप से भीड़ द्वारा संदेह के आधार पर किसी की हत्या करना, किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक जैसा है। ऐसे मामलों में पुलिस को भी अपना सूचना तंत्र मजबूत करने और संवेदनशील ढंग से कार्रवाई करने की जरूरत है। खासकर उस क्षेत्र के थाने की पुलिस व अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में संदेह के आधार पर किसी की जान लेने की प्रवृत्ति जिस तेजी से बढ़ रही है, वह हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। आये दिन हम सड़कों पर रोड रेज की घटनाएं सुनते और देखते हैं। सड़क में आगे निकलने की होड़ में गोली चलाने और हिंसक प्रतिरोध की घटनाएं अकसर सामने आती हैं। पिछले दिनों देहरादून में आगे निकलने की होड़ में दो कारों में सवार लोगों की गोलीबारी में सड़क पर सैर कर रहे सेना के एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की हत्या की घटना उत्तराखंड में व्यापक जनाक्रोश का विषय बनी। ऐसी घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि नई पीढ़ी के लोग अपना धैर्य, विवेक तथा संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। ये हमारे मानवीय मूल्यों व संवेदना का भी क्षरण है। दरअसल, हमारे समाज में संयुक्त परिवारों का बिखराव होने से बच्चों की संवेदनशील ढंग से परवरिश का न हो पाना भी युवाओं में बढ़ती आक्रामकता की वजह बन रहा है। पहले स्कूलों में शिक्षकों का दबदबा होता था और छात्र जीवन में अनुशासन का पाठ सीखते थे। मां-बाप के लाड़-प्यार और बच्चों को स्वच्छंद व्यवहार की आजादी ने उन्हें उच्छृंखल बनाया है। एकल परिवारों में पलने वाले अकेले बच्चों में दूसरों को आसानी से सहन न करने की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर समाज में लगातार जटिल होता जीवन भी उग्रता को बढ़ावा दे रहा है। नशा भी नाश का कारक बन रहा है। सूचना माध्यमों में बाजार द्वारा दर्शाए जा रहे विलासिता व भव्यता के सपने देखकर जब नई पीढ़ी कठोर यथार्थ से जूझती है तो हताशा के चलते उसमें आक्रोश के स्वर मुखर होते हैं। सिमटते रोजगार व मनमाफिक अवसर न मिलने की कुंठा भी उन्हें आक्रामक बना रही है। आज इन सभी कारकों को तुरंत संबोधित करने की जरूरत है।

नई सोच रोकेगी मनुष्यता के खिलाफ अपराध

> महाड के जल-सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है यह। वह सत्याग्रह वस्तुतः मानव-समाज की समानता के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। यह संघर्ष तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कानून या संविधान में दिये गये अधिकारों को सामाजिक स्तर पर पूरी मान्यता नहीं मिल जाती।

स्वतंत्रता सेनानी और अस्पृश्य समझे जाने वाले वर्ग के नेता बाबू जगजीवन राम को बचपन में स्कूल में इसलिए सज़ा मिली थी कि उन्होंने उस मटके से पानी पी लिया था जो स्कूल के सवर्ण अध्यापकों के लिए रखा गया था। यह बात तब की है जब हम गुलाम थे। पर ऐसे ही 'अपराध' के लिए स्वतंत्र भारत में भी नौ साल के एक दलित बच्चे को भी सज़ा मिली थी– राजस्थान के जालौर के एक स्कूल में उन बच्चों से भी अनजाने में ही अध्यापकों के मटके से पानी पीने का 'अपराध' हो गया था। यह घटना हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह के दिन घटी थी। दोनों ही घटनाओं में लगभग एक सदी की दूरी है। सदियों से दलितों के साथ इस तरह के अत्याचार होते आ रहे हैं। उम्मीद थी कि स्वतंत्र भारत में हमारी समाज व्यवस्था के माथे से यह कलंक मिट जायेगा। पर आज भी, यानी इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में इस आशय के समाचार मिल जाते हैं कि फलां गांव में या फलां कस्बे में दलित समाज के किसी व्यक्ति को इसलिए सज़ा भुगतान पड़ी कि उसने घोड़े पर बैठकर दूल्हा बनने का दुस्साहस किया था!

आज़ादी प्राप्त करने के बाद जब हमने अपना संविधान बनाया तो उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था की थी कि स्वतंत्र भारत में किसी भी नागरिक को अस्पृश्यता जैसे अभिशाप को झेलना न पड़े। एक लंबे संघर्ष के बाद यह स्थिति आयी थी, पर अभी भी अस्पृश्यता के अभिशाप से हम मुक्त नहीं हो पाये। सौ साल पहले बाबासाहेब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड में अगड़ों के लिए आरक्षित समझे जाने वाले एक तालाब से पानी पीने के अधिकार का संघर्ष शुरू किया था। उस तालाब में जानवर तो पानी पी सकते थे, पर अस्पृश्य समझे जाने वाले दलित को यह अधिकार नहीं था। ऊंची समझी जाने वाली जातियों के लोग यह मानते थे कि दलितों के छूने से वह भी अपवित्र हो जायेंगे। पता नहीं यह धारणा कब से चली आ रही है, पर यह एक शर्मनाक सच्चाई है कि हमारे देश में आज भी छुआछूत से हमारा पीछा नहीं छूट पाया। शहरी भारत में भले ही माथे पर यह कलंक न दिखता हो, पर ग्रामीण भारत आज भी जैसे इस त्रास को भोगने के लिए शापित है। यहां यह याद रखना ज़रूरी है कि लगभग अस्सी प्रतिशत भारत गांवों में बसता है!

सन् 1950 में हमने अपने संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की थी। हमारा संविधान कहता है, 'सरकार धर्म, जाति, जन्म आदि के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी'। लगता है, भेदभाव करने वालों ने मान लिया है कि यह व्यवस्था सरकार के लिए है, समाज के लिए नहीं! सौ साल पहले डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज को यह अहसास कराने की कोशिश की थी। सौ साल पहले 20 मार्च, 1927 को महाराष्ट्र के एक तालाब के पानी को न केवल दलितों ने छुआ, बल्कि उस तालाब का पानी पिया भी। वस्तुतः यह मनुष्यता की रक्षा के लिए किये जाने वाले एक संघर्ष की शुरुआत थी। यह सौवां वर्ष है इस संघर्ष का— और संघर्ष आज भी जारी है। हम इस बात पर तो गर्व कर सकते हैं कि सौ साल पहले ऐसा कोई संघर्ष प्रारंभ हुआ था, पर देखा जाये तो यह शर्म की ही बात है कि अब तक इस संघर्ष में पूरी विजय नहीं मिल पायी। पर इस असफलता से संघर्ष की महत्ता कम नहीं हो जाती। ज़रूरी है कि महाड में शुरू किये गये इस जल-सत्याग्रह की महत्ता को समझा जाये, इस संघर्ष को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाये। उस दिन अम्बेडकर के नेतृत्व में लगभग ढाई हज़ार दलितों ने महाड के चौदार तालाब के पवित्र समझे जाने वाले जल को अंजलि में भरकर एक नई आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत की थी। यह संघर्ष इस सिद्धांत को स्वीकारने के लिए भी था कि जल, जंगल और हवा प्रकृति ने हर प्राणी के लिए दिये हैं, किसी जन्म या किसी धर्म के नाम पर इनका बंटवारा नहीं हो सकता। किसी भी आधार पर प्रकृति के इन अवदानों पर कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता। पर इस बात को सवर्ण समझे जाने वाले समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। महाड सत्याग्रह से नाराज सवर्णों ने न केवल तालाब का 'शुद्धीकरण' किया, बल्कि सत्याग्रहियों को मारा-पीटा भी गया था। वे मामले को अदालत में भी लेकर पहुंचे। दस साल लगे न्यायालय को पानी पर सबके अधिकार का फैसला सुनाने में। और यह भी हकीकत है कि आज भी देश का एक बहुत बड़ा तबका मन से यह मानने को तैयार नहीं है कि दलितों को अस्पृश्य मानना मनुष्यता के खिलाफ एक अपराध है। सदियों से चले आ रहे इस अपराध का प्रायश्चित होना ही चाहिए। यह अपराध-बोध ही समता के इस संघर्ष को किसी तार्किक परिणति तक पहुंचा सकता है। महाड के जल-सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है यह। वह सत्याग्रह वस्तुतः मानव-समाज की समानता के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। यह संघर्ष तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कानून या संविधान में दिये गये अधिकारों को सामाजिक स्तर पर पूरी मान्यता नहीं मिल जाती। इस मान्यता को मिलने का मतलब है इस सत्य को स्वीकार करना कि किसी भी आधार पर मनुष्य और मनुष्य के बीच खाई नहीं होनी चाहिए। संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के चार स्तंभों पर एक मानवीय समाज की संरचना को आकार दिया गया है। अम्बेडकर ने जल-सत्याग्रह के माध्यम से समानता की लड़ाई को नया आयाम दिया था। चावदार तालाब के इस सत्याग्रह के तीन साल बाद उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों की समानता की लड़ाई का एक और मोर्चा खोला था। यहां विवाद दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर था। गांधीजी इससे दो दशक पहले दलितों को यह अधिकार दिये जाने के संघर्ष को प्रारंभ कर चुके थे। इतिहास की इन सारी बातों को याद करने का एक अवसर है जल-सत्याग्रह का यह शताब्दी वर्ष। इसे याद करने का मतलब समानता की एक अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ना है।

यह बात समझना ज़रूरी है कि समानता की यह लड़ाई किसी कानून या किसी सरकार के सहारे नहीं जीती जा सकती। आवश्यकता एक सामाजिक आंदोलन को चलाने, उसे गति देने की है। अम्बेडकर का जल-सत्याग्रह या गांधी का नमक-सत्याग्रह या दलित के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए किया गया मानवीय समानता का संघर्ष कुल मिलाकर समानता की एक ऐसी लड़ाई है जिसके पूरा हुए बिना मनुष्यता की लड़ाई किसी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकती। डाक्टर अम्बेडकर को हम संविधान के प्रमुख शिल्पी की तरह याद करते हैं। इस याद करने को सार्थक बनाने का अर्थ आदमी और आदमी के बीच की खाई को पाटना है। तीन साल पहले जारी किये गये एक आंकड़े के अनुसार देश में दलितों पर अत्याचार की पांच घटनाएं रोज घट रही हैं। जालौर के नौ साल के इंद्र मेघवाल के साथ हुआ अन्याय इन्हीं पांच में से एक है। यह अन्याय खत्म होना ही चाहिए– तभी मनुष्यता जीतेगी।

प्रेरणा

जब दिल जागता है: संवेदना से बनता सच्चा नेतृत्व

मनुष्य का जीवन केवल ज्ञान, शक्ति या उपलब्धियों से महान नहीं बनता, बल्कि उसकी असली पहचान उसके भीतर छिपी संवेदनशीलता से होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन व्यक्तियों ने दूसरों के दुःख को समझा, जिन्होंने अपमान के विरुद्ध आवाज उठाई और जिन्होंने करुणा को अपना धर्म बनाया, वही सच्चे अर्थों में महान बने। ऐसी ही एक प्रेरणादायक घटना उस समय की है, जब एक साधारण बालक चंद्रगुप्त, अपने गुरु चाणक्य के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था।

वह समय था जब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन को समझने की प्रक्रिया थी। गुरुकुल में प्रत्येक शिष्य को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उसे एक आदर्श मनुष्य और भविष्य का उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए तैयार किया जाता था। चाणक्य जैसे महान गुरु के सान्निध्य में शिक्षा पाना स्वयं में एक सौभाग्य था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और न्यायप्रिय भी बनाना चाहते थे। एक दिन गुरुकुल में एक ऐसी घटना घटी, जिसने चंद्रगुप्त के जीवन की दिशा बदल दी। एक निर्धन बालक, जिसकी आंखों में आंसू और मन में अपमान की पीड़ा थी, वहां आया। कुछ अन्य शिष्यों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके वस्त्र पुराने थे, उसकी स्थिति साधारण थी, परंतु उसकी भावनाएं उतनी ही गहरी थीं जितनी किसी और की। उस बालक का अपमान केवल उसकी गरीबी का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का अपमान था।

चंद्रगुप्त यह सब देख रहा था। उसने उस पीड़ा को महसूस भी किया, पर वह चुप रहा। उसका मौन उस समय शायद सामान्य प्रतीत हुआ, पर वही मौन आगे चलकर उसके लिए एक गहरा आत्मबोध बनने वाला था। वह समझ नहीं पाया कि उस क्षण उसे क्या करना चाहिए था—क्या उसे विरोध करना चाहिए था या चुप रहना चाहिए था। इसी द्वंद्व में उसने मौन को चुना।

लेकिन चाणक्य की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने इस पूरे दृश्य को देखा और समझ लिया कि यह केवल एक बालक का अपमान नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा का अवसर है। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, "जहां किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वहां ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि को विकसित करना नहीं, बल्कि हृदय को भी संवेदनशील बनाना है।"

उनके शब्दों में गहराई थी, और हर शिष्य के हृदय में उतर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, "यदि तुम दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते, यदि तुम किसी के दर्द को देखकर भी मौन रहते हो, तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। एक सच्चा मनुष्य वही है, जो दूसरों के सम्मान की रक्षा करे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।"

फिर उनकी नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी। उन्होंने उससे पूछा, "यदि तुम भविष्य में एक बड़े शासक बनो, लेकिन अपने ही लोगों के दुःख और भावनाओं को न समझ सको, तो क्या तुम एक स्थायी और न्यायपूर्ण राज्य बना पाओगे?" यह प्रश्न सीधा था, परंतु इसका प्रभाव गहरा था। यह केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि नेतृत्व का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि लोगों के हृदय को समझना है। चंद्रगुप्त के भीतर कुछ बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उसका मौन गलत था। उसने यह समझा कि अन्याय के सामने चुप रहना भी एक प्रकार का अन्याय है। उस क्षण उसने निर्णय लिया कि वह केवल दर्शक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि सही के पक्ष में खड़ा होगा।

वह तुरंत उस निर्धन बालक के पास गया। उसने उसके आंसू पोंछे, उसे सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाया और यह एहसास दिलाया कि वह अकेला नहीं है। उस छोटे से कार्य ने न केवल उस बालक के मन को शांति दी, बल्कि चंद्रगुप्त के भीतर एक नई चेतना का जन्म भी हुआ। समय के साथ चंद्रगुप्त ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उसने संघर्ष किया, अपने लक्ष्य के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः एक महान सम्राट बना। परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी युद्धक क्षमता नहीं थी, बल्कि उसकी संवेदनशीलता थी। वह अपने प्रजा के दुख को समझता था, उनके सम्मान की रक्षा करता था और न्याय को सर्वोपरि मानता था।

उसने यह सिद्ध किया कि एक सच्चा शासक वही होता है, जो अपने लोगों के दिलों में स्थान बना सके। तलवार से जीते हुए राज्य लंबे समय तक नहीं टिकते, परंतु प्रेम और सम्मान से जीते हुए दिल हमेशा साथ रहते हैं। चंद्रगुप्त का साम्राज्य केवल उसकी शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी करुणा और न्यायप्रियता का भी प्रतीक था। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। हम अपने जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जहां हमें निर्णय लेना होता है—क्या हम किसी के अपमान या अन्याय को देखकर चुप रहें, या उसके विरुद्ध खड़े हों। यही छोटे-छोटे निर्णय हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं।

संवेदना हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों के दर्द को महसूस करें, उनके साथ खड़े हों और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। यदि हम अपने जीवन में संवेदनशीलता को स्थान दें, तो हम न केवल अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने भीतर भी एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अंततः, जीवन की सच्ची सफलता यही है कि हम कितने लोगों के दिलों को छू पाए, कितनों के आंसू पोंछ पाए और कितनों को सम्मान दे पाए।

यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि महानता केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे संवेदनशील कार्यों में छिपी होती है। जब हम किसी के दर्द को समझते हैं और उसके सम्मान की रक्षा करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मानवता का पालन करते हैं।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि संवेदना ही वह शक्ति है, जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। यही वह गुण है, जो एक बालक को सम्राट बनाता है और एक व्यक्ति को सच्चा नेता बनाता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में कुछ सबसे मूल्यवान अपनाना चाहते हैं, तो वह है—दूसरों के प्रति सम्मान, करुणा और संवेदना।

होर्मुज संकट से बेहाल दुनिया को चीन की ऊर्जा नीति से सीख लेनी चाहिए

वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच एक सख्त सच्चाई उभर कर सामने आ रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडराते खतरे ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं, लेकिन इस उथल पुथल के बीच चीन एक अलग ही खेल खेलता नजर आ रहा है। जहां एशिया के कई देश ऊर्जा बचाने की अपील कर रहे हैं, वहीं चीन आत्मविश्वास से भरा हुआ है और दावा कर रहा है कि उसके पास ऊर्जा का पर्याप्त रणनीतिक भंडार है। दरअसल, यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया। चीन ने पिछले कई वर्षों में एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसने उसे वैश्विक तेल आपूर्ति के झटकों से काफी हद तक सुरक्षित बना दिया है। जब दुनिया तेल के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर है, चीन ने अपनी निर्भरता को योजनाबद्ध तरीके से कम किया है।

सबसे बड़ा बदलाव चीन के इलेक्ट्रिक वाहन अभियान में दिखता है। जहां 2020 में लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक नए वाहनों में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी, वहीं यह आंकड़ा अपेक्षा से कहीं आगे निकल गया और आधे से ज्यादा नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गईं। इसका सीधा असर यह हुआ कि चीन की तेल खपत अब स्थिर होने लगी है।

आंकड़े बताते हैं कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण जितना तेल बचा है, वह लगभग उतना ही है जितना चीन सऊदी अरब से आयात करता था। यह बदलाव मामूली नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा भू राजनीति की दिशा बदलने वाला संकेत है।

चीन की दूसरी सबसे बडी ताकत उसका विविधीकृत आयात तंत्र है। जहां जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश एक या दो आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं, वहीं चीन ने अपने तेल स्रोतों को आठ से ज्यादा देशों में फैला रखा है। रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों से सस्ता तेल लेकर उसने पश्चिमी प्रतिबंधों को भी अपने हित में बदल लिया है। रणनीतिक दृष्टि से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यदि किसी एक क्षेत्र में संकट आता है, तो चीन पूरी तरह ठप नहीं होगा।

तीसरा और सबसे खतरनाक दांव है चीन का विशाल तेल भंडार। अनुमान है कि उसके पास इतना तेल जमा है कि वह होर्मुज मार्ग बंद होने की स्थिति में करीब सात महीने तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। यह भंडारण केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि सामरिक हथियार भी है। देखा जाये तो ऊर्जा सुरक्षा के इस खेल में चीन ने केवल तेल पर ही भरोसा नहीं किया है। उसकी बिजली व्यवस्था लगभग आत्मनिर्भर हो चुकी है। कोयले और तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा के दम पर चीन ने अपने ग्रिड को बाहरी निर्भरता से लगभग मुक्त कर लिया है।

इसके साथ ही सौर और पवन ऊर्जा का विस्फोटक विस्तार इस बात का संकेत है कि चीन भविष्य की ऊर्जा लड़ाई के लिए पहले ही तैयार है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि उसे कम एलएनजी आयात करना पड रहा है और तटीय इलाकों की निर्भरता भी घट रही है। गैस के मामले में भी चीन ने चालाकी दिखाई है। पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए उसने रूस, मध्य एशिया और म्यांमार से सीधी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। इससे समुद्री मार्गों पर निर्भरता और कम हो गई है। सामरिक नजरिए से देखें तो यह पूरी रणनीति एक गहरी सोच का परिणाम है। चीन ने समझ लिया था कि भविष्य की जंग केवल हथियारों से नहीं बल्कि ऊर्जा पर नियंत्रण से जीती जाएगी।

आज जब होर्मुज जलडमरूमध्य पर खतरा मंडरा रहा है, तब भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन चीन इस संकट को अवसर में बदलने की स्थिति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की तेल मांग अब चरम पर पहुंचकर घटने की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में उसकी आयात निर्भरता और कम होगी, जिससे वैश्विक बाजार में उसकी स्थिति और मजबूत होगी।

बहरहाल, यह पूरा घटनाक्रम एक साफ संदेश देता है। जो देश समय रहते अपनी ऊर्जा रणनीति नहीं बदलेंगे, वे आने वाले संकटों में बुरी तरह फंस सकते हैं। चीन ने यह साबित कर दिया है कि दीर्घकालिक योजना, आक्रामक निवेश और रणनीतिक विविधीकरण के दम पर किसी भी वैश्विक संकट को मात दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया इस सबक को समझेगी या फिर अगला संकट उन्हें पूरी तरह झकझोर देगा।

अभियान

भक्ति की पराकाष्ठा: जब हजारों वर्षों की तपस्या ने भगवान को पुत्र बनने का वचन दिलाया

भारतीय अध्यात्म की गहराइयों में ऐसी अनेक कथाएँ छिपी हैं, जो केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाले दिव्य संदेश हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत पावन प्रसंग उस समय का है, जब महर्षि याज्ञवल्क्य अपने शिष्य और महान ऋषि भरद्वाज को श्रीरामकथा का रसपान करा रहे थे। वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक था, जहाँ हर शब्द में भक्ति का माधुर्य और हर भाव में ईश्वर के प्रति प्रेम झलक रहा था। भरद्वाज मुनि अत्यंत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रहे थे, जैसे उनके हृदय में हर प्रसंग एक जीवंत चित्र के रूप में अंकित हो रहा हो।

नारद से संबंधित प्रसंग के पश्चात याज्ञवल्क्यजी ने एक अत्यंत अद्भुत और गहन कथा का वर्णन प्रारंभ किया—यह कथा थी मनु और शतरूपा की, जिनकी तपस्या और भक्ति ने स्वयं भगवान को उनके जीवन में पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए बाध्य कर दिया। मनु, जिन्हें सम्पूर्ण मानव जाति का आदिपुरुष माना जाता है, केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा के सजीव स्वरूप थे। उनकी पत्नी शतरूपा भी पतिव्रत धर्म, सादगी और उच्च आदर्शों की मूर्ति थीं। उनका जीवन इतना पवित्र था कि वेद भी उनके आचरण का गुणगान करते हैं। मनु ने अपने जीवन का अधिकांश समय एक आदर्श शासक के रूप में बिताया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ न्याय किया, धर्म का पालन किया और समाज में संतुलन बनाए रखा। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध। परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया और वृद्धावस्था निकट आई, उनके भीतर एक गहरी बेचैनी उत्पन्न होने लगी। यह बेचैनी किसी भौतिक वस्तु की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि आत्मा की उस प्यास के कारण थी, जो केवल ईश्वर के साक्षात्कार से ही शांत हो सकती है।

धीरे-धीरे यह भावना वैराग्य में परिवर्तित हो गई। मनु को यह अनुभव होने लगा कि संसार का हर सुख क्षणिक है, और यदि जीवन प्रभु के दर्शन के बिना समाप्त हो जाए, तो वह अधूरा रह जाता है। इस गहन अनुभूति ने उन्हें एक बड़ा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ वन की ओर प्रस्थान कर दिया। यह केवल बाहरी त्याग नहीं था, बल्कि उनके भीतर की आसक्तियों का भी पूर्ण परित्याग था।

वन में उनका जीवन अत्यंत कठिन था। वहाँ कोई सुख-सुविधाएँ नहीं थीं, केवल तप, त्याग और संघर्ष था। फिर भी उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। वे नैमिषारण्य के पवित्र वन, गोमती नदी के तट और अनेक ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करते रहे। हर स्थान पर उन्होंने कठोर तपस्या की और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा किया। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी—प्रभु के साक्षात् दर्शन।

समय के साथ उनकी तपस्या और भी तीव्र होती गई। उन्होंने पहले भोजन का त्याग किया और केवल जल पर जीवन यापन करने लगे। फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर हो गए। अंततः उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक कठोर तप में लीन रहे। यह तपस्या केवल शरीर की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह उनके मन, आत्मा और श्रद्धा की भी परीक्षा थी।

उनकी इस अद्वितीय तपस्या को देखकर त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु और महेश—भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कई बार उनकी परीक्षा ली, विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न किए, परंतु मनु और शतरूपा का मन कभी विचलित नहीं हुआ। उनका लक्ष्य स्पष्ट था और उनकी भक्ति अडिग। यह केवल तप नहीं था, बल्कि वह प्रेम था, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती—केवल समर्पण होता है।

अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। आकाश में एक दिव्य वाणी गूँजी—"वर मांगो।" यह वाणी उनके जीवन की साधना का प्रतिफल थी। उस क्षण उनका शरीर, जो तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण हो गया था, पुनः तेजस्वी और सशक्त हो उठा। उनके भीतर एक नई ऊर्जा और आनंद का संचार हुआ। मनु ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ कहा—"हे प्रभु! जिनका गुणगान वेद करते हैं, जिनके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का मुनिजन ध्यान करते हैं, हम उन आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात् दर्शन करना चाहते हैं। कृपा कर हमें अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें।" उनकी वाणी में न कोई अहंकार था, न कोई स्वार्थ—केवल निष्कपट भक्ति थी।

उनकी इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उनका श्यामवर्ण शरीर नीलकमल और मेघ के समान मनोहर था। उनके मुख पर ऐसी शांति और करुणा थी, जो हर हृदय को आकर्षित कर ले। उनकी मुस्कान में प्रेम था, उनके नेत्रों में अनंत करुणा झलक रही थी।

भगवान ने स्नेहपूर्वक कहा—"हे मनु! मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी इच्छा हो, निःसंकोच कहो।" यह सुनकर मनु भावविभोर हो गए। उन्होंने कहा—"प्रभु! आपके दर्शन से अब कोई इच्छा शेष नहीं रही। फिर भी, यदि आप कृपा करें, तो हमें आपके समान एक पुत्र प्राप्त हो।"

यह सुनकर भगवान मुस्कराए और बोले—"हे मनु! मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, अतः मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा।" यह वचन केवल एक वरदान नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा थी। यह उस भक्ति का प्रतिफल था, जिसने भगवान को भी अपने भक्त के प्रति समर्पित कर दिया।

शतरूपा ने भी प्रभु से अटूट भक्ति और उनके चरणों में अनन्य प्रेम का वरदान माँगा। भगवान ने दोनों को उनकी इच्छानुसार वरदान प्रदान किया और अंतर्धान हो गए। यह क्षण उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि था, जब उनकी तपस्या और प्रेम ने ईश्वर को भी उनके जीवन का हिस्सा बना दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। परंतु उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। अगले जन्म में वे त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। उसी जन्म में भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए श्रीराम के रूप में उनके पुत्र बनकर अवतार लिया और अपनी दिव्य लीलाओं से संसार को धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया।

यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि मन में अटूट विश्वास और प्रेम हो, तो ईश्वर भी हमारे जीवन में उतर आते हैं। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सूरत में चुनावी तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार: निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन सख्त, हर स्तर पर माइक्रोप्लानिंग पर जोर

सूरत। आगामी स्थानीय स्वशासन चुनावों को लेकर सूरत जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में जिला कलेक्टर कार्यालय में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी ने की। इस बैठक में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी प्रमुख अधिकारियों—नोडल अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ)—को स्पष्ट संदेश दिया गया कि चुनाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर काम तय समयसीमा के भीतर पूरी सटीकता के साथ पूरा होना चाहिए।

बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि पूरे जिले में मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। कलेक्टर ने अधिकारियों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल औपचारिक तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि हर स्तर पर माइक्रोप्लानिंग की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बूथ स्तर तक की व्यवस्थाओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि किसी भी मतदाता को असुविधा का सामना न करना पड़े और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।

इस समीक्षा बैठक के समानांतर राज्य स्तर पर भी तैयारियों की निगरानी की जा रही है। एस. मुरलीक्रिष्णा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें सूरत जिला भी सक्रिय रूप से शामिल रहा। इस संवाद के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि सभी जिलों में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का एक समान और प्रभावी क्रियान्वयन हो।

बैठक में चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सख्त पालन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी भी प्रकार के अवैध होर्डिंग्स या प्रचार सामग्री को तत्काल हटाया जाए और चुनावी माहौल को स्वच्छ एवं निष्पक्ष बनाए रखा जाए। इसके साथ ही चुनावी स्टाफ की नियुक्ति, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से तय करने पर भी जोर दिया गया, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी इस बैठक का एक प्रमुख विषय रहा। प्रशासन ने निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और एमसीसी टीमों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए, ताकि किसी भी तरह की चुनावी गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन को तुरंत रोका जा सके। इसके अलावा पोलिंग स्टाफ की तैनाती, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और मतदान सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी विस्तृत योजना तैयार करने को कहा गया।

तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के सुरक्षित प्रबंधन, स्ट्रांग रूम की निगरानी और चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्वीप (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) कार्यक्रम के जरिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें।

गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए भी प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई है। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर पंडाल या छायादार स्थान की सुविधा और उचित लाइटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे आराम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर विजय रबारी सहित 41 से अधिक नोडल अधिकारी, आरओ और एआरओ उपस्थित रहे, जो यह दर्शाता है कि प्रशासन इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीरता से तैयारी कर रहा है। अंत में जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों से समन्वय और जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह त्रुटिरहित और विश्वसनीय बन सके।

कुल मिलाकर, सूरत में चुनावी तैयारियों ने अब पूरी गति पकड़ ली है। प्रशासनिक स्तर पर सख्ती, तकनीकी प्रबंधन और जमीनी स्तर पर की जा रही सूक्ष्म योजना यह संकेत देती है कि इस बार चुनाव को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन तैयारियों का वास्तविक असर मतदान के दिन किस रूप में सामने आता है।

पश्चिमी यूपी में बड़ी मुठभेड़: 50 हजार का इनामी शूटर आशु चड्ढा उर्फ मोंटी ढेर, 36 मुकदमों का हिस्ट्रीशीटर खत्म

मुरादाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बीच बुधवार देर रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात शार्प शूटर आशु चड्ढा उर्फ मोंटी को मुठभेड़ में मार गिराया। लंबे समय से फरार चल रहा यह आरोपी उधम सिंह गैंग से जुड़ा हुआ था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसकी मौत को पुलिस अपराध जगत के लिए एक बड़ा झटका और कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है।

बताया जा रहा है कि मोंटी हाल ही में मुरादाबाद के एक निर्यातक से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित था। इस घटना के बाद से ही वह पुलिस की नजर में था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। एसटीएफ की मेरठ इकाई और स्थानीय पुलिस की टीम कई दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और उसकी लोकेशन ट्रैक करने में जुटी थी।

बुधवार देर रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित पोस्टमार्टम हाउस के पास उसकी मौजूदगी की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही पुलिस टीम आरोपी के करीब पहुंची, उसने खुद को घिरता देख अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मोंटी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी कार्रवाई को बेहद योजनाबद्ध और तेज बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने जोखिम उठाते हुए आरोपी को निष्क्रिय किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के अनुसार, मोंटी मूल रूप से हापुड़ जिले का निवासी था और पिछले कई वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उसके खिलाफ गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और मुरादाबाद समेत कई जिलों में हत्या, रंगदारी, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के कुल 36 मुकदमे दर्ज थे। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि वह न केवल एक शार्प शूटर था, बल्कि एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का अहम हिस्सा भी था।

पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक कार, .32 बोर की पिस्टल, रिवॉल्वर और 12 बोर की बंदूक के साथ बड़ी संख्या में कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं। यह बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था या फिर पहले से ही हथियारों के साथ पूरी तरह लैस होकर चल रहा था।

इस एनकाउंटर के बाद पुलिस अब मोंटी के पूरे आपराधिक नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि उसके कई सहयोगी अभी भी सक्रिय हो सकते हैं, जो अलग-अलग जिलों में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को केवल एक व्यक्ति के खात्मे के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे पूरे गिरोह के खिलाफ एक बड़ी शुरुआत माना जा रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से संगठित अपराध और गैंगवार की घटनाओं के लिए चर्चा में रहा है। ऐसे में इस तरह की सटीक और त्वरित कार्रवाई पुलिस की रणनीति में आए बदलाव को भी दर्शाती है, जहां अब अपराधियों को पकड़ने या उन्हें निष्क्रिय करने के लिए तकनीक और खुफिया जानकारी का अधिक प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है।

फिलहाल, इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। प्रशासन का साफ संदेश है कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है और कानून से बचना अब पहले जितना आसान नहीं रहा।

सूरत: विशाखापत्तनम में नौसेना अधिकारी द्वारा प्रेमिका की हत्या का चौंकाने वाला मामला

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

वह काले सिर वाला आदमी दिन-ब-दिन और भी विकृत और हत्यारा होता जा रहा है। क्या होगा, कहाँ होगा और कब होगा? और कौन क्या करेगा और कब होगा? इस कलियुग में यह जानना मुश्किल है। और फिर भी, किसके मन में क्या चल रहा है? यह जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है।

इसके बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भी ऐसी ही एक जघन्य घटना घटी। पता चला है कि भारतीय नौसेना (आईएनएस देगा) के 30 वर्षीय अधिकारी चिंतदा रविंद्र ने अपनी 31 वर्षीय प्रेमिका पोलिपल्ली मौनिका की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके फ्रिज में छिपा दिए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रेम कहानी की शुरुआत एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। पुलिस जांच के अनुसार, रविंद्र और मौनिका का संपर्क 2021 में "मिंगल" नामक डेटिंग ऐप के जरिए हुआ था। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ और वे अक्सर मिलते थे। हालांकि, 2024 में रविंद्र ने दूसरी महिला से शादी कर ली। इसके बाद दोनों के बीच

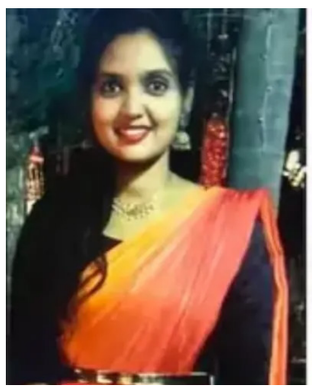

दरार शुरू हो गई। रविंद्र का आरोप है कि मौनिका ने उनसे 3.5 लाख रुपये लिए थे और उनकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में बताने की धमकी देकर उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रही थी।

इससे तंग आकर रविंद्र ने अपनी पत्नी के दोस्त के घर जाने का फायदा उठाया और दोपहर में मौनिका को अपने घर बुलाया। शाम तक दोनों के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर रविंद्र ने मौनिका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू मंगवाया और शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। उसने पैर और धड़ को एक ट्रॉली बैग में पैक किया और धड़ को फ्रिज में छिपा दिया, जबकि माना जाता है कि उसने सिर और हाथों को कहीं और ले जाकर जला दिया।

इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने के बाद रविंद्र खुद पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और फ्रिज और घर से शव के टुकड़े बरामद किए। हालांकि, मौनिका का सिर अभी तक नहीं मिला है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लापता अंगों की तलाश के लिए एक विशेष टीम गठित की है। यह मामला एक बार फिर आफताब पूनावाला द्वारा श्रद्धा वॉकर की हत्या की याद दिलाता है, जिसने दिल्ली में काफी हलचल मचाई थी।

धारावी हत्याकांड की गूंज बिहार तक: शव पहुंचते ही फूटा गुस्सा, हाईवे जाम कर ग्रामीणों ने मांगा इंसाफ

पटना/शिवहर। मुंबई के धारावी इलाके में हुई एक युवक की हत्या ने सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के शिवहर जिले में ऐसा आक्रोश पैदा कर दिया, जिसने पूरे इलाके की शांति को झकझोर कर रख दिया। गुरुवार तड़के जैसे ही 25 वर्षीय धीरज कुमार ठाकुर का शव उसके पैतृक गांव वैद्यनाथपुर पहुंचा, वैसे ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते शोक का माहौल उग्र विरोध में बदल गया और लोगों ने शिवहर-तरियानी-मीनापुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाए गए, लोग शव के साथ धरने पर बैठ गए और पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

धीरज कुमार ठाकुर, जो तरियानी थाना क्षेत्र के वैद्यनाथपुर गांव के निवासी थे, कुछ समय से मुंबई में रहकर काम कर रहे थे। 30 मार्च की सुबह धारावी के माहिम फाटक इलाके में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन जब शव गांव पहुंचा तो दुख के साथ-साथ गुस्सा भी उभरकर सामने आ गया।

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप ले गया। आरोप है कि आरोपितों ने मिलकर धीरज को घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जब उसके भाइयों ने विरोध करने की कोशिश की, तो उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वे घायल हो गए। इस पूरी घटना ने परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है।

इस मामले में मृतक के भाई नीरज कुमार ठाकुर ने मुंबई के शाहुनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में ओसामा मकसूद अली शेख, आवेश कलीम शाह, अज्जू यासीन शेख और मोहम्मद अरमान सुभान चौधरी सहित कई लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया है।

शव के गांव पहुंचते ही लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उन्हें न्याय और उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और गंभीर आरोप सामने आया है—मुंबई पुलिस पर लापरवाही का। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि घटना के बाद न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी परिवार से मिलने पहुंचा और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध ली। यही वजह है कि लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। उनका कहना है कि यदि समय रहते संवेदनशीलता दिखाई जाती, तो शायद स्थिति इतनी बिगड़ती नहीं।

हालात बिगड़ते देख स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को धीरे-धीरे नियंत्रित किया गया, लेकिन इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होने से होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार संकट में है, विकल्प तलाश शुरू हो गई है।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। केंद्र सरकार द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमत में अचानक 195.50 रुपये की बढ़ोतरी से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद यह दूसरी बढ़ोतरी है। अब, व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के महंगे होने से कई होटल, रेस्तरां और खानपान व्यवसाय बंद होने की कगार पर हैं।

ऊपर दी गई तस्वीर में दिखाए गए अनुसार, कई होटल मालिकों ने कोयले से चलने वाले फायरप्लेस का उपयोग करना शुरू कर दिया है और अपना व्यवसाय जारी रखा है। इसके अलावा, कई अन्य लोगों ने भी विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक फायरप्लेस का उपयोग करना शुरू कर दिया है और अपना व्यवसाय जारी रखा है। इसके अलावा, वे और क्या कर सकते हैं?

दुनिया के टेलीकॉम मानचित्र पर भारत की ताकत: दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी एयरटेल, 65 करोड़ ग्राहकों का विशाल नेटवर्क

नई दिल्ली। वैश्विक दूरसंचार जगत में भारत की मौजूदगी लगातार मजबूत होती जा रही है और इसी कड़ी में Bharti Airtel ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए मोबाइल ग्राहक संख्या के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम और तकनीकी विकास का भी प्रतीक है। कंपनी का कुल ग्राहक आधार अब 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो इसे वैश्विक स्तर पर एक बेहद मजबूत खिलाड़ी बनाता है।

यह रैंकिंग GSMA के 'जीएसएमए इंटेलिजेंस' के आंकड़ों पर आधारित है, जो 31 मार्च तक के वैश्विक मोबाइल उपभोक्ता डेटा का विश्लेषण करता है। इस सूची में एयरटेल का दूसरे स्थान पर पहुंचना यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं।

एयरटेल की इस सफलता के पीछे उसका व्यापक और रणनीतिक विस्तार है। भारत में जहां उसके 36.8 करोड़ से अधिक मोबाइल ग्राहक हैं, वहीं अफ्रीका के 14 देशों में भी कंपनी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, जहां उसके करीब 17.9 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। अफ्रीका के कई देशों में एयरटेल ने न केवल मोबाइल सेवाएं दी हैं, बल्कि वहां की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी गति दी है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क पहुंचाकर कंपनी ने करोड़ों लोगों को पहली बार इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा है।

कंपनी अब पारंपरिक मोबाइल सेवाओं से आगे बढ़कर भविष्य की तकनीकों में भी निवेश कर रही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एयरटेल की एंट्री इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए कंपनी ने Eutelsat OneWeb और SpaceX के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है, जहां अभी तक पारंपरिक नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। यह पहल खासतौर पर पहाड़ी इलाकों, दूरस्थ गांवों और समुद्री क्षेत्रों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।

एयरटेल के कार्यकारी उपाध्यक्ष Gopal Vittal ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंपनी का मुख्य फोकस नवाचार, सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करना है। उनका मानना है कि भविष्य में प्रतिस्पर्धा सिर्फ ग्राहक संख्या की नहीं, बल्कि बेहतर अनुभव और अत्याधुनिक सेवाएं देने की होगी। अगर भारत के दूरसंचार बाजार की बात करें तो यह दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। यहां इस समय कुछ ही बड़ी कंपनियां पूरे बाजार पर हावी हैं। Reliance Jio के पास लगभग 47–48 करोड़ ग्राहक हैं, जो इसे देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर बनाते हैं। इसके बाद एयरटेल का स्थान आता है, जबकि Vodafone Idea (Vi) के पास करीब 21–22 करोड़ ग्राहक हैं। सरकारी क्षेत्र की कंपनी BSNL और MTNL के संयुक्त ग्राहक लगभग 8–9 करोड़ के आसपास हैं।

भारत में कुल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 115 से 120 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो इस बात का संकेत है कि देश में डिजिटल पहुंच कितनी व्यापक हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अब ग्रामीण भारत भी तेजी से इंटरनेट और स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है। यही कारण है कि भारत आज डेटा उपभोग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। 4G तकनीक ने जहां डिजिटल क्रांति की नींव रखी, वहीं अब 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। 5G के जरिए न सिर्फ इंटरनेट की गति बढ़ेगी, बल्कि स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंचाने पर विशेष ध्यान दे रही हैं, जिससे डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके।

इस पूरे परिदृश्य में एयरटेल की यह उपलब्धि यह दिखाती है कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली नहीं, बल्कि उसे दिशा देने वाली बन चुकी हैं। आने वाले समय में जब सैटेलाइट इंटरनेट, 5G और डिजिटल सेवाओं का और विस्तार होगा, तब एयरटेल जैसी कंपनियां न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के डिजिटल भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगी।

चेहरा धोने के नियम , सलाह और सावधानियां -शहनाज़ हुसैन

चेहरा धोना त्वचा की देखभाल का सबसे आसान काम लगता है। साफ़ सुथरी और आकर्षक त्वचा पाने की चाहत में हम दिन में बार बार चेहरा धोते हैं। सही तरीके से चेहरा धोने से हमारी त्वचा ताजा , साफ़ और स्वास्थ्य दिखती है लेकिन लगभग 80 प्रतिशत लोग चेहरा धोने में गलतियाँ करते हैं और कुछ तो हर घण्टे चेहरा धोते हैं लेकिन इसके बाबजूद उनकी त्वचा नीरस , डल और बेजान सी दिखती है जिसकी बजह से बह निराश ,परेशान से दिखते हैं। दरअसल चेहरा धोते समय की गई कुछ गलतियों की बजह से हमारी त्वचा को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचता है और ज्यादातर लोग यह गलतियां अनजाने में कर बैठते हैं।

1 ------मेरी यह सलाह है की चेहरा धोने से पहले अपने हाथों को साबुन से जरूर साफ़ कर लें। हमारे हाथ निरन्तर बैक्टीरिया , तेल और गन्दगी के सम्पर्क में आते रहते हैं। गन्दे हाथों से चेहरा धोने से गन्दगी चेहरे पर फैल सकती है जिससे चेहरे के रोमछिद्र बंद हो जाते है और कील , मुहांसे निकल आते हैं। इससे त्वचा सम्बन्धी अनेक समस्याएं हो सकती हैं।

2 ----चेहरे को गर्म पानी से धोने से बचें। गर्म पानी से चेहरा धोने से त्वचा की प्रकृतिक नमी खतम हो जाती है। इस सूखेपन से निपटने के लिए त्वचा ज्यादा तेल स्त्रावित करने लगती है जोकि कील मुहांसों का कारण बनता है। अगर आप ठंडे पानी से चेहरा धोते हैं तो त्वचा के छिद्र सिकुड़ जाते है जिसकी बजह से चेहरा सही तरह से साफ़ नहीं हो पाता है। अगर आप कील मुहांसो से परेशान हैं तो ठन्डे पानी से मुंह धोने से परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि ठंडा पानी त्वचा की सूजन जरूर कम करता है लेकिन मुहांसों से होने बाली सूजन को कम नहीं कर सकता। इसलिए चेहरा धोने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और चेहरा रगड़ने की बजाय थपथपाकर सुखाएं। गुनगुना पानी रोमछिद्रों को खोलकर चेहरे से तेल और गंदगी को पूरी तरह हटा देता है और चेहरे के प्रकृतिक तेल और नमी को भी बनाए रखता है। सर्दियों में त्वचा को कोमल और मुलायम बनाये रखने के लिए गुनगुना पानी सबसे बेहतर माना जाता है।

3 -----चेहरे को धोने के लिए ज्यादा फेस वॉश का उपयोग नुकसान पहुंचा सकता हैं। ज्यादा फ ेस वॉश लगाने से त्वचा का नेचुरल आयल खतम हो जाता है और त्वचा रूखी रूखी लगने लगती है। चेहरा धोने के लिए मटर के दाने के बराबर फेस वाश काफी होता है। इसे अपनी हथेली पर डाल कर आपस में रगड़ कर झाग बनाएं और साफ़ उँगलियों की मदद से गीले चेहरे पर समान रूप से लगाएं। इसे आहिस्ता से गोलाकार गति में लगाएं क्योंकि इसके जोर से रगड़ने से त्वचा में घाव हो सकते हैं। इसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो डालें। फेस वॉश का चयन करती बार अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखें क्योंकि गलत फेस वॉश इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। रूखी त्वचा की लिए क्रीम आधारित फेस वॉश और संबेदनशील त्वचा के लिए माइल्ड क्लेंज़र का उपयोग करना चाहिए

4 ------मेरा यह मानना है की दिन में में चेहरे को सुबह और शाम दो बार धोना बेहतर होता है। सुबह चेहरा धोने से रात की गंदगी और आयल क्लीन हो जाता है जबकि शाम को चेहरा धोने से दिन भर की धूल ,मिट्टी और प्रदूषण हट जाता है

बार बार चेहरा धोना त्वचा को नुकसानदायक हो सकता है। अगर चेहरा धोने के बाद आपकी त्वचा रूखी और खिंची -खिंची सी लगती है और आप बार बार चेहरा धो रहे हैं क्योंकि बार बार चेहरा धोने से चेहरे का प्रकृतिक तेल और नमी गायब हो जाती है जिससे चेहरे की सुरक्षा परत कमजोर पढ़ जाती है।

चेहरा धोने में कम से कम एक मिनट तो लगाना ही चाहिए ताकि चेहरे की सारी मैल और गन्दगी निकल जाये। आप चाहे तो दो या तीन मिनट भी लगा सकते हैं ताकि त्वचा को पूरा समय मिल सके। मेरा यह मानना है की चेहरा धोने का कोई मानक तय नहीं किया गया है बल्कि यह स्किन टाइप पर निर्भर करता है।

5 ----चेहरा धोने के साथ सुखाना भी जरूरी होता है। चेहरा सुखाने के लिए मुलायम सूती साफ़ तौलिये का इस्तेमाल करें। गंदे तौलिये पर बैक्टीरिया हो सकते हैं जोकि आपकी त्वचा पर जम जायेंगे जोकि रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं जिससे मुहांसे और त्वचा की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।आप चाहें तो त्वचा को प्रकृतिक तौर पर भी सूखने दे सकते हैं। तौलिये से त्वचा को हल्के से थपथपाकर सुखाएं और रगड़ने से परहेज करें खासकर अगर आपकी त्वचा संवेदनसील , रूखी और कील मुहांसों से ग्रसित हो। चेहरा सुखाने के लिए आप फेस वाइप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो लेकिन इसके नियमित परहेज से बचें। इनमें प्रेजर्वेटिव होते हैं जोकि त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेखिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेष्ज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है।

हिंडन एयरपोर्ट की उड़ानों पर अचानक ब्रेक, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें और एयरलाइंस के फैसले के पीछे की पूरी कहानी

दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और निराशाजनक खबर सामने आई है। जिस एयरपोर्ट को पिछले वर्ष क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से बड़े उत्साह के साथ शुरू किया गया था, वही अब धीरे-धीरे अपनी रफ्तार खोता नजर आ रहा है। हाल ही में मुंबई, अहमदाबाद और पटना जैसे प्रमुख शहरों के लिए यहां से संचालित होने वाली उड़ानों को अचानक बंद कर दिया गया है। इस फैसले ने न केवल यात्रियों को झटका दिया है, बल्कि हिंडन एयरपोर्ट के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हिंडन एयरपोर्ट से अपना पूरा ऑपरेशन समेट लिया है, जबकि इंडिगो ने भी अपनी उड़ानों की संख्या में भारी कटौती कर दी है। कभी इस एयरपोर्ट से करीब 16 शहरों के लिए लगभग 50 उड़ानें संचालित होती थीं, लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 7 शहरों और लगभग 14 उड़ानों तक सिमट गई है। इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ा है, जो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बचने के लिए हिंडन एयरपोर्ट को एक सुविधाजनक विकल्प मानते थे।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के संचालन बंद करने के साथ ही मुंबई, अहमदाबाद और पटना जैसे बड़े शहरों की सीधी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। इसके अलावा भटिंडा, लुधियाना और किशनगढ़ जैसे शहरों के लिए उड़ानों पर भी असर पड़ा है। यह बदलाव खासतौर पर उन यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है, जो समय

और लागत दोनों बचाने के लिए हिंडन एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते थे।

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई तकनीकी और व्यावसायिक कारण सामने आए हैं। सबसे बड़ा कारण हिंडन एयरपोर्ट की परिचालन सीमाएं हैं। यह एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के एयरबेस के भीतर स्थित है, जिसके चलते यहां नागरिक उड़ानों के लिए कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि यहां केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही उड़ानें संचालित की जा सकती हैं। रात के समय फ्लाइट संचालन की अनुमति नहीं होने के कारण एयरलाइंस के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, यहां संसाधनों की भी कमी बताई जा रही है। सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के कारण बड़े पैमाने पर उड़ान संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। एयरलाइंस कंपनियां आमतौर पर उन रूट्स को प्राथमिकता देती हैं, जहां यात्रियों की संख्या अधिक हो और मुनाफा सुनिश्चित हो सके। लेकिन हिंडन एयरपोर्ट फिलहाल इन मानकों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। कम यात्री संख्या और सीमित संचालन समय के चलते एयरलाइंस को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्होंने अपने ऑपरेशन कम करने या बंद करने का फैसला लिया। सर्दियों के मौसम में कोहरे की समस्या भी इस एयरपोर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। कम विजिबिलिटी के कारण अक्सर उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है और एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ता है। बार-बार उड़ान रद्द होने से यात्रियों का भरोसा भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, जो किसी भी एयरपोर्ट के लिए एक गंभीर संकेत है।

हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि एयरलाइंस ने यह निर्णय अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है और इसमें एयरपोर्ट प्रबंधन की कोई सीधी भूमिका नहीं है। हालांकि, प्रबंधन यह भी दावा कर रहा है कि वे लगातार एयरलाइंस कंपनियों के संपर्क में हैं और भविष्य में यहां सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इस फैसले का सबसे अधिक असर गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में रहने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। अब उन्हें मुंबई, अहमदाबाद या पटना जैसे शहरों की यात्रा के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का रुख करना पड़ेगा। इससे न केवल यात्रा का समय बढ़ेगा, बल्कि अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा। खासकर पीक ट्रैफिक के समय दिल्ली तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हिंडन एयरपोर्ट को फिर से सक्रिय और प्रभावी बनाना है, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन प्रणाली में सुधार करना होगा। साथ ही, रात के समय उड़ानों की अनुमति जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि एयरलाइंस कंपनियों को यहां संचालन में सुविधा मिल सके। इसके अलावा, यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और प्रचार-प्रसार की भी जरूरत है।

फिलहाल, हिंडन एयरपोर्ट का यह हाल क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजनाओं के सामने एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यह दिखाता है कि केवल एयरपोर्ट बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मजबूत योजना, पर्याप्त संसाधन और व्यावसायिक दृष्टिकोण भी उतना ही जरूरी होता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिंडन एयरपोर्ट एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ पाता है या फिर यह धीरे-धीरे हवाई नक्शे से गायब होने लगता है।

रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,अमित जोगी करें आत्मसमर्पण

प्रदेश कांग्रेस (जे) कमेटी के अध्यक्ष हैं अमित जोगी, निचली अदालत द्वारा मिली राहत को किया निरस्त

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद एक बड़ा और अहम मोड़ सामने आया है। Chhattisgarh High Court ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष Amit Jogi को बड़ा झटका देते हुए निचली अदालत से मिली राहत को निरस्त कर दिया है। अदालत की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अमित जोगी तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करें। इस फैसले ने राज्य की राजनीति और कानूनी हलकों में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha और न्यायमूर्ति Arvind Verma की खंडपीठ ने यह निर्णय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी Central Bureau of Investigation (सीबीआई) की अपील पर सुनवाई करते हुए सुनाया। अदालत ने इस दौरान मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयान और विस्तृत साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्य इस मामले में गंभीरता को दर्शाते हैं और निचली अदालत द्वारा दिया गया निर्णय न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

इस केस में सीबीआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष लगभग 11 हजार पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें घटना से

जुड़े तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। इस व्यापक दस्तावेज के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अमित जोगी के खिलाफ पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषसिद्धि की श्रेणी में मानते हुए आत्मसमर्पण का आदेश जारी किया। फैसले के तुरंत बाद अमित जोगी ने इसे अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि वे इस निर्णय को Supreme Court of India में चुनौती देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे अपने पक्ष को सर्वोच्च अदालत के समक्ष मजबूती से रखेंगे। गौरतलब है कि यह मामला 4 जून 2003 का है, जब रायपुर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और कोषाध्यक्ष Ramavatar Jaggi की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उस समय पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था और इसे छत्तीसगढ़ की सबसे सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं में गिना गया। वर्ष 2007 में विशेष अदालत ने इस मामले में 28 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि अमित जोगी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस प्रकरण में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो ने सरकारी गवाह बनकर मामले को नई दिशा दी। बाद में इस केस को लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील की गई, जहां से इसे पुनः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को भेजा गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद अब यह ताजा फैसला सामने आया है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अधिवक्ता वैभव ए. गोवर्धन ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ता सतीश जग्गी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.पी. शर्मा उपस्थित रहे। राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल डॉ. सौरभ पांडे और अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रमोद कुमार वर्मा ने भी अपनी दलीलें पेश कीं। सभी पक्षों की विस्तृत बहस के बाद अदालत ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।

रामावतार जग्गी का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव काफी व्यापक था। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री Vidyacharan Shukla के करीबी माने जाते थे और उनके साथ कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे। पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके चलते उनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में बनी थी। उनकी हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति में काफी उथल-पुथल मच गई थी और यह मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा।

अब उच्च न्यायालय के इस फैसले ने एक बार फिर इस पुराने लेकिन अहम मामले को सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमित जोगी सर्वोच्च न्यायालय में किस तरह से अपनी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाते हैं और इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। फिलहाल, अदालत के स्पष्ट निर्देश के बाद उनकी अगली कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

सूरत में ट्रैफिक पर बड़ा असर: रिंग रोड कनेक्टिंग मार्ग एक महीने के लिए बंद, डायवर्जन से बदलेगा शहर का यातायात पैटर्न

सूरत। तेजी से विकसित हो रहे सूरत शहर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों के बीच अब आम नागरिकों को एक महीने तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा। सूरत नगर निगम ने न्यू ईस्ट (सरथाना) जोन में टी.पी. स्कीम नंबर 84 के तहत स्टॉर्म बॉक्स नालियों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत रिंग रोड को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह निर्णय न केवल यातायात को प्रभावित करेगा, बल्कि शहर के रोजमर्रा के जीवन पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा।

नगर निगम आयुक्त एम. नागराजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार गोपिन सर्किल जंक्शन पर बाहरी रिंग रोड से जुड़ने वाली टी.पी. रोड को 15 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक सभी प्रकार के वाहनों और यहां तक कि पैदल यात्रियों के लिए भी पूर्णतः बंद रखा जाएगा। यह कदम बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 236 (1) और (2) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उठाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह फैसला प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह वैध और आवश्यक माना गया है।

दरअसल, जिस स्टॉर्म बॉक्स नालियों के निर्माण की बात की जा रही है, वह शहर के जल निकासी तंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद अहम है। सूरत जैसे शहर में, जहां हर साल मानसून के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है, वहां इस तरह

की परियोजनाएं दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रिंग रोड के दोनों ओर इन नालियों का निर्माण किया जाना है, ताकि बारिश के पानी का निकास तेज और व्यवस्थित तरीके से हो सके। हालांकि, इस काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पूरे मार्ग को बंद करना अनिवार्य हो गया है।

मार्ग बंद होने से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने विस्तृत डायवर्जन प्लान तैयार किया है। नंद चौक (मोटा वराछा) से रिंग रोड की ओर जाने वाले वाहनों को अब मोटा वराछा-अब्रामा चेक पोस्ट फोर रोड का उपयोग करना होगा, जहां से वे बाएं मुड़कर कष्टभंजन चौक के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसी तरह, रिंग रोड से नंद चौक की ओर जाने वाले वाहनों को भी कष्टभंजन चौक से अंदरूनी मार्गों का सहारा लेना होगा।

अब्रामा गांव की दिशा से आने-जाने वाले वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। अब्रामा से रिंग रोड की ओर जाने वाले वाहन गोपिन रिवर विले श्री रोड से दाएं मुड़कर प्रमुख एक्सोटिका फोर रोड के जरिए आगे बढ़ेंगे। वहीं रिंग रोड से अब्रामा की ओर जाने वाले वाहनों को कष्टभंजन चौक और अन्य वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना होगा। इन सभी डायवर्जन मार्गों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रैफिक का दबाव संतुलित रहे और जाम की स्थिति को न्यूनतम किया जा सके।

हालांकि, इतने बड़े स्तर पर मार्ग बंद होने का असर शहर के दैनिक जीवन पर पड़ना तय है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल-कॉलेज के छात्र, व्यापारिक गतिविधियों में लगे लोग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करना होगा। ट्रैफिक जाम, यात्रा समय में वृद्धि और वैकल्पिक मार्गों पर बढ़ते दबाव जैसी समस्याएं शुरुआती दिनों में देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें।

नगर निगम का कहना है कि यह अस्थायी असुविधा भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगी। जब यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तो न केवल जल निकासी की समस्या में सुधार होगा, बल्कि सड़क की संरचना भी अधिक मजबूत और टिकाऊ बनेगी। इससे आने वाले वर्षों में मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों में काफी कमी आने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, यह परियोजना सूरत के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और नागरिकों के बीच समन्वय बेहद जरूरी होगा। अगले एक महीने तक शहर की सड़कों पर बदलते ट्रैफिक पैटर्न के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि लोग किस तरह इस बदलाव को अपनाते हैं और प्रशासन किस हद तक व्यवस्था को सुचारू बनाए रख पाता है।

कोयला तस्करी केस में ED का बड़ा एक्शन, IPAC के ठिकानों पर देशभर में छापेमारी

नई दिल्ली/कोलकाता/बेंगलुरु। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए देश के कई शहरों में छापेमारी की है। Enforcement Directorate (ED) ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म Indian Political Action Committee (IPAC) से जुड़े ठिकानों पर रेड की है। यह कार्रवाई हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली सहित कई स्थानों पर एक साथ की गई, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।

जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु में कंपनी के को-फाउंडर Rishiraj Singh के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। इससे पहले भी इसी वर्ष जनवरी में ED ने कोलकाता स्थित IPAC कार्यालय और इसके डायरेक्टर Prateek Jain के आवास पर छापेमारी की थी। उस समय कंपनी ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण और कठिन दिन" बताते हुए कहा था कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी कानून का सम्मान करते हुए सहयोग जारी रखेगी।

दरअसल, यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़ा है, जिसकी जांच Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा दर्ज 2020 की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। इसके बाद ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी Prevention of Money Laundering Act के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि Eastern Coalfields Limited (ECL) के लीज क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कोयले की खुदाई और चोरी की जा रही थी।

ED की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड Anup Majhi था, जो लंबे समय से अवैध खनन और चोरी किए गए कोयले के परिवहन का नेटवर्क चला रहा था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे रैकेट में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है, जिनमें ECL, Central Industrial Security Force (CISF), भारतीय रेलवे और अन्य विभागों से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं।

जांच के दौरान यह सामने आया कि ECL क्षेत्र से अवैध खनन और चोरी के जरिए लगभग 2,742.32 करोड़ रुपये के कोयले की हेराफेरी की गई। ED ने यह भी बताया कि इस काले कारोबार का पूरा हिसाब-किताब रखने के लिए अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। अनुप माजी के खिलाफ वर्ष 2000 से 2015 के बीच 16 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, लेकिन प्रभाव और संरक्षण के चलते लंबे समय तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।

इस केस में हवाला नेटवर्क का भी बड़ा खुलासा हुआ है। ED के अनुसार, अवैध कोयला कारोबार से अर्जित काले धन को सफेद करने के लिए हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी दावा किया गया कि करीब 20 करोड़ रुपये की हवाला राशि IPAC तक पहुंचाई गई थी। हालांकि, इन आरोपों पर कंपनी ने पहले ही कहा है कि वह पूरी तरह कानून का पालन करती है और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है।

ED ने पहले जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच भी इस मामले में 46 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान गुरुपदा माजी और जयदेव मंडल जैसे सहयोगियों के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई के लेन-देन के प्रमाण सामने आए थे। साथ ही शकंभरी ग्रुप ऑफ कंपनियों को अवैध कोयले की बिक्री के भी साक्ष्य मिले थे।

इस पूरे मामले में राजनीतिक विवाद भी कम नहीं रहा है। पहले की छापेमारी के दौरान ED ने Mamata Banerjee पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कार्रवाई में हस्तक्षेप किया और अहम दस्तावेजों को हटाने में पुलिस की मदद ली। हालांकि, इन आरोपों को लेकर राजनीतिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। गौरतलब है कि IPAC देश की एक प्रमुख पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म रही है, जिसने विभिन्न विचारधाराओं वाली कई राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है।

3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक शाहीबाग अंडरपास यातायात के लिए बंद रहेगा

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल अंतर्गत शाहीबाग अंडरपास नंबर 731A के सभी प्रवेश एवं निकास मार्ग 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के कारण यातायात हेतु बंद रहेंगे।

इस अवधि के दौरान मार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक मार्ग निम्नानुसार रहेंगे:

1. दिल्ली दरवाजा एवं सुभाष ब्रिज की ओर से आने वाला ट्रैफिक, जिसे एयरपोर्ट या गांधीनगर जाना है, वह सुभाष ब्रिज के अंत में शिलालेख फ्लैट होकर रिवरफ्रंट मार्ग का उपयोग करते हुए डफनाला होते हुए एयरपोर्ट तथा गांधीनगर जा सकेगा।
2. एयरपोर्ट-गांधीनगर की ओर से आने वाला ट्रैफिक डफनाला रिवरफ्रंट मार्ग का उपयोग कर विभिन्न मार्गों की ओर जा सकेगा। साथ ही असारवा, गिरधरनगर, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर जाने के लिए शाहीबाग होते हुए महाप्रज्ञजी ब्रिज का उपयोग किया जा सकेगा।
3. गिरधरनगर-असारवा की ओर से आने वाला ट्रैफिक, जिसे गांधीनगर या एयरपोर्ट जाना है, वह शाहीबाग होते हुए एनेक्सी, गायत्री मंदिर, आर्मी कैंटोनमेंट मार्ग से होकर एयरपोर्ट तथा इंदिरा ब्रिज, गांधीनगर की ओर जा सकेगा।

सोना वायदा में 4503 रुपये और चांदी वायदा में 15784 रुपये की भारी गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा 1011 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 155629.99 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 41081.71 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 114547.64 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 35679 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3580.49 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 29779.06 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 146832 रुपये के भाव पर खूलकर, 149699 रुपये के दिन के उच्च और 145601 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 150104 रुपये के पिछले बंद के सामने 4503 रुपये या 3 फीसदी गिरकर 145601 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 4139 रुपये या 3.38 फीसदी गिरकर 118250 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 517 रुपये या 3.37 फीसदी गिरकर 14809 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 148480 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 148679 रुपये और नीचे में 144612 रुपये पर पहुंचकर, 5588 रुपये या 3.7 फीसदी गिरकर 145238 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 151200 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151200 रुपये और नीचे में 146000 रुपये पर पहुंचकर, 152443 रुपये के पिछले बंद के सामने 5022 रुपये या 3.29 फीसदी गिरकर 147421 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 242800 रुपये के भाव पर खूलकर, 242800 रुपये के दिन के उच्च और 224500 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 243501 रुपये के पिछले बंद के सामने 15784 रुपये या 6.48 फीसदी लुढ़ककर 227717 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 15157 रुपये या 6.15 फीसदी की गिरावट के साथ 231280 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 15201 रुपये या 6.17 फीसदी लुढ़ककर 231349 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कमोडिटी वायदाओं में 41081.71 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 114547.64 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 29779.06 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 35679 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 2336.96 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 20.05 रुपये या 1.71 फीसदी गिरकर 1149.15 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 4.25 रुपये या 1.31 फीसदी गिरकर 321.15 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 4.85 रुपये या 1.36 फीसदी औंधकर 350.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 1.4 रुपये या 0.71 फीसदी गिरकर 196.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 8817.32 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 9623 रुपये के भाव पर खूलकर, 10286 रुपये के दिन के उच्च और 9623 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1011 रुपये या 10.93 फीसदी की तेजी के संग 10264 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 1007 रुपये या 10.88 फीसदी की बढ़त के साथ 10263 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 270 रुपये के भाव पर खूलकर, 272.7 रुपये के दिन के उच्च और 267.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 265.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.8 रुपये या 1.43 फीसदी की मजबूती के साथ 269.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 3.6 रुपये या 1.36 फीसदी की बढ़त के साथ 269.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 1046 रुपये पर खूलकर, 60 पैसे या 0.06 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1030 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 20553.33 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9225.73 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1548.29 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 485.43 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 28.16 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 275.08 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7208.88 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1564.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 7715 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 47512 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26883 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 381123 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 52841 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7300 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 20096 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 79524 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 23357 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 35174 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 35822 पॉइंट पर खूलकर, 35940 के उच्च और 35679 के नीचले स्तर को छूकर, 1095 पॉइंट घटकर 35679 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 517.8 रुपये की बढ़त के साथ 1030.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2 रुपये की बढ़त के साथ 15.25 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 279 रुपये की गिरावट के साथ 533 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 562.5 रुपये की गिरावट के साथ 997.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.31 रुपये की गिरावट के साथ 15.07 रुपये हुआ। जस्ता मई 342.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.59 रुपये की गिरावट के साथ 1.11 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 292 रुपये की गिरावट के साथ 352.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.6 रुपये की गिरावट के साथ 16.2 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 193.5 रुपये की बढ़त के साथ 457.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 53 रुपये की बढ़त के साथ 599 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.41 रुपये की बढ़त के साथ 14.52 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 26 पैसे के सुधार के साथ 5.25 रुपये हुआ।